# DAILY NEWS BULLETIN

## LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day

**Tuesday** **20260609**

सकते हैं।

0.04 मिलियन वर्ग किमी हो गया।

शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।

**समस्या** | पहले से ब्लॉकेज, बीपी और मधुमेह से जूझ रहे मरीजों पर ज्यादा आफत, पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से डिहाइड्रेशन की बनी स्थिति

# दिल पर सितम, थर्मल स्ट्रेस से अचानक बढ़े हार्ट अटैक

■ आशीष दीक्षित

कानपुर। कहर बरपाती गर्मी पसीना ही नहीं छुड़ा रही, दिल पर दबाव भी डाल रही है। तापमान में बढ़ोतरी और उमस के चलते शरीर थर्मल स्ट्रेस की चपेट में आ रहा है। यही वजह है कि हार्ट अटैक के मामलों में अचानक उछाल आ गया है।

हृदय रोग संस्थान कानपुर के आंकड़ों के मुताबिक दो महीने में हार्ट अटैक के मामलों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी, मार्च में जहां रोज 10 से 12 ऐसे मरीज आते थे, अप्रैल और मई में यह संख्या 18 से 20 पहुंच गई है। पूर्वांचल और बरेली में भी थर्मल स्ट्रेस के दिल पर दुष्प्रभाव के मामले सामने आए हैं। हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सामान्य नहीं, बल्कि गर्मी से जुड़े फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का परिणाम है। भीषण गर्मी के दौरान शरीर पर पड़ने वाला यह दबाव रक्त संचार और हृदय की कार्यप्रणाली दोनों को प्रभावित करता है, जिससे अचानक अटैक का जोखिम बढ़ जाता है।

सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर देखा जा रहा है जो पहले से हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं। करीब 40 प्रतिशत मामले 30 से 45 वर्ष की उम्र से जुड़े हैं, जो लंबे समय तक गर्म वातावरण में काम करने और पानी की कमी के कारण जोखिम में आ गए।

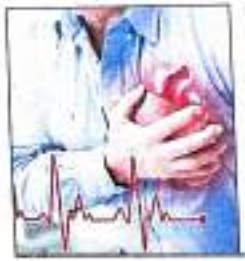

**30%** हार्ट अटैक हृदय रोग संस्थान में दो माह के भीतर बढ़े

**40%** 30 से 45 वर्ष के आयु वाले, ज्यादा देर गर्मी से दिक्कत

### कब पहुंचें अस्पताल

मसवानपुर निवासी 42 वर्षीय निजी कंपनी के कर्मचारी को दोपहर में तेज धूप में काम के दौरान सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई।

### इन लक्षणों पर करें गौर

सीने पर दबाव या दर्द, सांस फूलना अचानक पसीना, चक्कर या बेहोशी अनियमित धड़कन, हाथ-जबड़े में दर्द

### इन टिप्स पर करें अमल

1. पर्याप्त पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स लें
2. तेज धूप से बचें, हल्का भोजन
3. बीपी और शुगर को नियंत्रित रखें

**दिल का गर्मी से क्या कनेक्शन, जानिए:** हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ. आरके वर्मा के अनुसार थर्मल स्ट्रेस के दौरान शरीर का कूलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे अधिक पसीना निकलता है। इस प्रक्रिया से शरीर में तेजी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटैशियम) की कमी हो जाती है। इसके बाद डिहाइड्रेशन से शरीर में तरल पदार्थ कम होने से ब्लड वॉल्यूम घटने लगता है।

अध्ययन

जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के मौसम में भी बढ़ रही चिपचिपाती गर्मी

# चार दशक में चार गुना क्षेत्रों तक बढ़ा उमस भरी गर्मी का दायरा

नई दिल्ली। भारत में गर्मी के मौसम (मार्च-जून) के दौरान कई बार असहनीय चिपचिपाहट से लोगों का परेशान हो जाना आम बात रही है। लेकिन अब मानसून के मौसम (जुलाई-अक्तूबर) में भी ऐसी ही बेहाल कर देने वाली गर्मी की अवधि बढ़ती जा रही है। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण सिर्फ इस असहनीय ऊष्मा तनाव (यूएचएस) वाले दिनों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, बल्कि इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।

अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (एजीयू) एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन 1980 से 2020 के बीच आए बदलावों के बारे में बताता है। इसके मुताबिक, 1980 के दशक में भारत में करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर (तकरीबन त्रिपुरा के बराबर क्षेत्रफल) असहनीय ऊष्मा तनाव से प्रभावित था लेकिन चार दशकों में यह दायरा बढ़कर 40,000 किलोमीटर हो गया है। अध्ययन के मुताबिक, असहनीय गर्मी का प्रकोप मार्च-जून के महीनों में अधिक पाया गया, जिससे भारत का आठ प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ और यह वार्षिक गर्मी से संबंधित मृत्यु दर से भी जुड़ा है। मानसून के मौसम में केवल एक प्रतिशत क्षेत्र ही प्रभावित पाया गया। अध्ययन में यह आगाह भी किया गया है कि वैश्विक तापमान 2 डिग्री के करीब पहुंचने के साथ भारत में मानसून के दौरान गर्म और उमस भरी परिस्थितियां असहनीय गर्मी की स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बनाती जाएंगी। जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ने और औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने पर भारत में असहनीय ऊष्मा तनाव लगभग उतने ही क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा जितना कि गर्मी के मौसम में करेगा। ब्यूरो



## बीमारियां बढ़ने और उत्पादकता घटने का खतरा

अध्ययन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर और अमेरिका के स्टैनफोर्ड और पर्ड्यू विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने कहा कि गर्मी और मानसून दोनों मौसमों में लंबे समय तक, असहनीय गर्मी घनी आबादी वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु लचीलेपन के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। यही नहीं, गर्मी के कारण श्रम साध्य क्षेत्रों में उत्पादकता घटने का भी खतरा है।

**जानलेवा साबित हो सकती है गर्मी से जुड़ी बीमारियां**

अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से काफी पसीना निकलता है। यह पसीना जब सूखता है, तो शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन जब उमस की वजह से पसीना सूख नहीं पाता तो यही असहनीय ऊष्मा तनाव का कारण बन जाता है।

police (traffic) Dinesh information about ro- navigation platforms.

monsoon season, when sudden waterlogging, emergency repairs and traffic diversions frequently affect key arterial roads across the city.

Officials said the new mechanism is expected to reduce the burden on courts by introducing a digital grievance

ance, grievance proceedings, payments and final disposal, creating a transparent digital trail.

# "How these twins are taking on invisible pollutants in water with low-cost device

Meghna.Dhulia@timesofindia.com

## SYSTEM DOESN'T NEED ELECTRICITY

Plant-based water purification system developed by Class XII twin sisters

Designed to remove microplastics and PFAS or 'forever chemicals' from drinking water

Developed and tested at the biomass laboratory, IIT Delhi

**HOW DOES IT WORK?**

**STEP 1 — Basic Filtration**
Water is first filtered to remove visible impurities

**STEP 2 — Microplastic Removal**
Natural polymers from okra and fenugreek bind with microplastic particles

**STEP 3 — PFAS Removal**
Rice husk biochar adsorbs PFAS compounds from water

**STEP 4 — Cleaner Water**
Treated water contains significantly lower levels of microplastics and PFAS

**TEST RESULTS**

1. Up to 93% removal efficiency across 20 PFAS compounds
2. Patent awaited

**COST AND ACCESSIBILITY**

1. **Estimated cost:** ₹100 for a pack of 10 sachets
2. Requires no electricity
3. No technical expertise required
4. Intended as a low-cost alternative to RO purifiers

Nayantara Singh (left) and Naina Singh after finishing third and being declared as Water Champions during an event held at IIT Madras last month

**New Delhi:** As concerns over contaminated drinking water continue to grow across India, a promising solution has emerged not from a research facility but from the curiosity and determination of teenage twin sisters from Delhi-NCR.

Alarmed by reports of declining groundwater quality and the growing presence of invisible pollutants in water sources, Naina and Nayantara Singh spent nearly a year developing a low-cost filtration system made from common agricultural ingredients. Their aim was to create a solution capable of removing both microplastics and PFAS, which are toxic substances often referred to as "forever chemicals" because they do not easily break down in the environment or the human body and can persist for years, without the high-cost conventional purification technologies.

"When we came across a Delhi govt study highlighting groundwater depletion across all districts of the city, we felt it was a problem that deserved action," Nayantara said. That concern soon evolved into their scientific journey. "We first began working on the idea when we were in Class XI, and it took nearly a year to reach meaningful results," Naina recalled.

The sisters, now in Class XII at Step by Step School, Noida, eventually developed Aqua Sattva, a plant-based water filtration system under their student startup, Hydra Nova. The innovation combines an okra-fenugreek polymer and rice husk biochar in easy-to-use sachets resembling tea bags. Made entirely from plant-derived, biodegradable materials sourced from agricultural produce and waste, the sachets require no electricity, plumbing, maintenance or technical expertise, making them particularly relevant for households that cannot afford expensive purification systems.

Priced at an estimated Rs 100 for a pack of 10 sachets, it is designed as an affordable alternative to reverse osmosis purifiers, which cost between Rs 10,000 and Rs 30,000. The sisters are currently awaiting a patent.

"Most effective solutions rely on RO systems, which are expensive, require electricity and also waste significant amounts of water," said Nayantara. "We wanted to develop something that could work for ordinary households. The objective was to make safe drinking water more accessible and affordable."

Building the project required balancing scientific research with the demands of school life. "We couldn't neglect our studies, so it was a constant exercise in balancing school and research," the sisters said. "At one stage, we were travelling to the laboratory two or three times a week. We also utilised our winter break. Whenever one of us was tied up with academic commitments, the other would keep the project moving."

The prototype was developed and tested at the biomass laboratory of Indian Institute of Technology Delhi under the guidance of professor Vivek Kumar. Independent laboratory testing showed that it achieved up to 93% removal efficiency across 20 different PFAS compounds after basic filtration. Additional testing using stereomicroscopy also indicated a substantial reduction in microplastic density in treated water samples.

The science behind the innovation is relatively simple. Natural polysaccharides found in okra and fenugreek bind and trap microplastic particles through flocculation. Rice husk biochar, which is produced from agricultural residue that is often burned in fields, adsorbs PFAS compounds from water.

Kumar, who works in the field of environmental engineering and industrial sustainability, said the project stood out because it tackled a pressing challenge through a practical and scalable approach.

The sisters' scientific temperament, according to their mother Gopika Kaul, has been evident since childhood. "Both of them have always been deeply inclined towards science and are endlessly curious," she said. "They have always wanted to understand why problems exist and how they can be solved."

Their work has already attracted national and international recognition. Last month, the sisters were named Water Champions 2026 at Stockholm Junior Water Prize India, a student science contest focused on water sustainability. Competing against more than 350 teams, they secured third place at the national finals held at IIT Madras. They have also earned a distinction at Conrad Challenge, a global entrepreneurship and innovation competition.

# अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीखें

**पौराणिक कथाओं और साहित्य में हंस को 'नीर क्षीर विवेकी' कहा गया है। यानी अगर पानी और दूध को मिला दिया जाए, तो उसमें से वह केवल दूध ग्रहण करता है। इस प्रकार हमें भी अच्छे-बुरे के सागर से केवल अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए।**

अध्यात्म
आचार्य तुलसी

[illegible]

## हेय और उपादेय का विवेक

[illegible]



[illegible]

## दुष्ट मनोवृत्ति पर लगाम लगाएं

[illegible]

## पूर्व धारणा बनाने से बचें

[illegible]

## विचारभेद हो, मनभेद नहीं

[illegible]

401 500

है। एसीबी ने साफ कर दिया है कि था। कई महत्वपूर्ण टेंडरों से जुड़ा अचानक तेजी से मंजूरी दी गई।

# तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने किया बेहाल

राज्य ब्यूरो, जागरण● नई दिल्ली: मौसम के बदले मिजाज के बीच तेज धूप में उमस भरी गर्मी एक बार फिर दिल्लीवासियों का हाल बेहाल कर रही है। हीट इंडेक्स तापमान से कहीं ज्यादा दर्ज हो रहा है, तो बिना एसी के राहत नहीं मिल पा रही। कूलर व पंखे बेअसर से हो गए हैं। मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिन और ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

साफ आसमान और दिन भर खिली रही तेज धूप में सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि हीट इंडेक्स 43.2 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 60 से 22 प्रतिशत दर्ज किया गया।

मंगलवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ रहेगा। धूप निकली रहेगी। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 43 और 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद बृहस्पतिवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट लेगा। तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इससे तापमान में भी कमी आएगी। बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। दोनों दिनों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच एनसीआर में पहुंचने की संभावना है। मानसून केरल में चार जून को पहुंचा, जो आमतौर पर एक जून को आता है, यानी उससे तीन दिन बाद। दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने का अनुमान है।

सोमवार को दोपहर में तेज धूप में सिर कपड़े से ढककर जाते राहगीर● जागरण

**42.2** डिग्री सेल्सियस के तापमान में 43.2 डिग्री की महसूस हुई गर्मी

## सोमवार को दर्ज तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

| | | |
|---|---|---|
| सफदरजंग | 42.2 | 29.2 |
| पालम | 41.8 | 25.5 |
| लोधी रोड | 42.6 | 27.8 |
| रिज क्षेत्र | 43.4 | 27.0 |
| आयानगर | 41.6 | 25.2 |
| नजफगढ़ | 40.5 | 27.7 |

महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नहीं आए

इस्तीफे की मांग की जाएगी।

# प्रोटीन के चक्कर में बाल खाए, करानी पड़ी सर्जरी

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

**बचपन मे** सुनी एक बात 24 साल के युवक के लिए बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई। परिवार के अनुसार उसे बचपन में बताया गया था कि बालों में प्रोटीन होता है। इसी धारणा के चलते उसमें बाल खाने की आदत विकसित हो गई। वर्षो तक चली यह आदत आखिरकार इतनी खतरनाक साबित हुई कि उसके पेट में बालों का 9 सेंटीमीटर का बड़ा गुच्छा जमा हो गया और उसे ऑपरेशन कराना पड़ा।

**24 साल की उम्र में पेट से निकला 9 सेंटीमीटर का गुच्छा**

इलाज के लिए पहुंचे आकाश हॉस्पिटल के सीनियर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. शरद मल्होत्रा ने बताया कि युवक पिछले दो से तीन महीनों से सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द, मतली और बेचैनी की शिकायत से परेशान था।

**दुर्लभ बीमारी ने पेट में जमा किए बाल**

डॉक्टरो के मुताबिक वह ट्राइकोबेजोआर नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। इस स्थिति मे निगले गए बाल पेट मे जमा होते रहते है और धीरे-धीरे एक ठोस गांठ का रूप ले लेते है। शरीर इन्हे न तो पचा पाता है और न ही स्वाभाविक रूप से बाहर निकाल सकता है।

माता-पिता से नही मिला, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की FIR

# जुड़वा बच्चियों का चेहरा देख हुआ शक, DNA ने खोला राज़

Abhishek.Gautam1
@timesofindia.com

AI Image

NBT एक्सक्लूसिव

- आईवीएफ के जरिए दिया था जन्म, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
- मोहन गार्डन के रहने वाले है पीड़ित, द्वारका के अस्पताल मे हुई डिलिवरी

■ नई दिल्ली : जनवरी 2026 को मोहन गार्डन की एक महिला ने द्वारका के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में दो बच्चों को जन्म दिया। पिता समेत परिवार के कई सदस्यों ने बच्चियों के फेस को देखा तो शक हुआ। जिसके बाद दंपती ने डीएनए टेस्ट कराया और बेटियों का डीएनए मैच नही हुआ। इसका खुलासा होते हुए पूरा परिवार गहरा सदमा लगा। दंपती का आरोप है कि जब इसकी शिकायत नामी अस्पतालों से की तो उल्टा नामी अस्पताल ने दंपती पर ही कई आरोप लगा दिए। दंपती की मांग है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री, पीएमओ, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर कई संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्रेटर कैलाश के एक नामी आईवीएफ सेंटर से दिसंबर 2024 में उन्होंने और उनकी पत्नी का IVF इलाज शुरू कराया था। अस्पताल की ओर से भरोसा दिलाया गया कि पूरी प्रक्रिया में केवल उनके ही स्पर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब डिलिवरी का समय आया तो उन्हें डिलिवरी के लिए द्वारका के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में डिलिवरी की सलाह दी गई। जिसके बाद महिला को नामी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया ने बताया कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। जनवरी 2026 में जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ और परिवार में खुशियां छा गई, लेकिन जन्मी बेटियों का फेस देख दंपती को शक हुआ। इसके बाद कराई गई दो अलग-अलग DNA जांचों ने कथित तौर पर ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में बच्चों का न तो पिता और न ही मां से बायोलॉजिकल मैच हुआ। इसके राहुल ने बताया कि इसकी शिकायत जहां आईवीएफ का इलाज और जहां डिलिवरी हुई, दोनों ही अस्पताल से इसकी शिकायत की गई।

## पांच महीने से खुद के बच्चे की कर रहे तलाश

पीड़ित बताते है कि उनके पहले से ही दो बेटिया है। डीएनए मैच न होने के बाद से वह लगातार खुद के बच्चे की तलाश मे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मे भटक रहे है। उनका आरोप है कि शुरुआती तीन महीने तक एफआईआर नही हुई। फिर साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर विडियो डालकर यह मांग की है कि जिन दंपती की जनवरी मे उस नामी अस्पताल मे डिलिवरी हुई है वह अपने बच्चो की डीएनए टेस्ट जरूर कराएं। उनका आरोप है कि भ्रूण या बच्चे का अदला-बदली हुई है। ऐसे मे यह गंभीर मामला है। उनकी मांग है कि इस मामले की हर स्तर तक जांच होनी चाहिए।

# मानसून के दौरान लंबी हो सकती है गर्मी और उमस

## अंदेशा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** दुनियाभर के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो भारत में मानसून के दौरान गर्मी और उमस की अवधि लंबी हो सकती है। आईआईटी गांधीनगर और अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शोध में दावा किया है जो अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (एजीयू) में प्रकाशित हुआ है।

मानसून सीजन के दौरान असहनीय उष्मा में तेज बढ़ोतरी दिख सकती है। गर्मी और मानसून में लंबे समय तक अनकम्पेन्सेबल हीट स्ट्रेस की स्थिति रहती है तो इससे घनी आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य, श्रम उत्पादकता और जलवायु तंत्र को नुकसान हो सकता है।

**क्या है अनकम्पेन्सेबल हीट स्ट्रेसः** अनकम्पेन्सेबल हीट स्ट्रेस वह स्थिति है, जब अत्यधिक गर्मी और नमी के कारण मानव शरीर पसीने या अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए खुद को ठंडा नहीं कर पाता। शरीर में लगातार गर्मी जमा होने से हीट स्ट्रोक, अंग काम करना बंद कर सकते हैं, मौत भी हो सकती है।

### मार्च से जून तक प्रभावी

मार्च से जून के बीच गर्मी के बीच यह हीट स्ट्रेस देश के लगभग आठ फीसदी क्षेत्र को प्रभावित करता था। गर्मी से होने वाली मौतों का भी बड़ा कारक बना है। मानसून में केवल एक फीसदी क्षेत्र ही प्रभावित था।

### कई क्षेत्र प्रभावित

मानसून में अनकम्पेन्सेबल हीट स्ट्रेस की घटनाएं खासतौर से पंजाब और देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वी तटीय क्षेत्र ऐसे प्रमुख हॉटस्पॉट बने हैं।

**बढ़ा हीट स्ट्रेस का दायराः** शोध के अनुसार 1979 से 2021 के बीच भारत में अनकम्पेन्सेबल हीट स्ट्रेस की घटनाओं में तेजी आई है। 1980 में यह प्रभाव 0.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम था, जो 2020 तक बढ़कर 0.04 मिलियन वर्ग किमी हो गया।

और बेचैनी की शिकायत से परेशान था।

रूप से बाहर निकाल सकता है।

**उठे कई सवाल** दोनो बच्चो का बायोलॉजिकल संबंध माता-पिता से नही मिला, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की FIR

# IVF से जन्मीं बेटियां, DNA का मिलान नहीं

Abhishek.Gautam1
@timesofindia.com

AI image

- पीएमओ से लेकर कई विभागो मे दंपती ने की है शिकायत
- कोई कार्रवाई नही होने के चलते पांच महीने से न्याय के लिए भटक रहे

## भ्रूण या बच्चा बदलने के आरोप की जांच शुरू

जांच मे दंपती का बायोलॉजिकल संबंध नही मिला। इसके बाद दंपती ने कोई कार्रवाई नही होने पर साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दंपती ने भ्रूण या बच्चे बदलने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। दंपती ने इस मामले की शिकायत पीएमओ से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कई संबंधित विभाग से की है।

■ नई दिल्ली: संतान पाने की उम्मीद मे IVF का सहारा लेने वाले एक दंपती की खुशियां उस वक्त सदमे मे बदल गईं, जब जुड़वां बेटियो के जन्म के बाद कराई गई DNA जांच मे कथित तौर पर दोनो बच्चो का बायोलॉजिकल संबंध माता-पिता से नही मिला। दंपती ने भ्रूण और बच्चा बदलने का आरोप लगाया, जिसके बाद वह कोर्ट गए और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, केस दर्ज किए 2 महीने बीत गए। लेकिन अब तक दंपती को खुद के बच्चे नही मिले। दंपती लगातार अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रहे है।

NBT Exclusive

मोहन गार्डन निवासी एक दंपती ने बताया कि उनकी पत्नी का आईवीएफ का इलाज ग्रेटर कैलाश इलाके के एक नामी आईवीएफ सेंटर मे हुआ था, जबकि डिलीवरी जनवरी मे द्वारका के एक नामी प्राइवेट अस्पताल मे हुई। जहां महिला ने दो बेटियो को जन्म दिया। दंपती को शक हुआ तो उन्होने बेटियो का डीएनए टेस्ट कराया।

# रेगिस्तानी हवाओं ने फिर बढ़ाई राजधानी में तपिश

- 42.2 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान
- गुरुवार के बाद मौसम के बदलाव का अनुमान

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** दिल्ली फिर से सूखी रेगिस्तानी हवाओं की चपेट में आ गई। इसके चलते दिल्ली के तमाम हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। हालांकि, राहत की बात यह है कि दो दिन बाद धूल भरी आंधी और बौछारें पड़ने की संभावना है।

दिल्ली में सोमवार सुबह दस बजे के बाद से धूप बेहद तीखी होने लगी। 12 बजे के बाद तो गर्म हवा के थपेड़ों का भी अहसास होने लगा। दिल्ली के एक छोटे हिस्से में रविवार को हल्की बूंदाबांदी और बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन तेज धूप के चलते दिल्ली की हवा में नमी का स्तर बेहद कम हो गया है।

दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत ने बताया कि दिल्ली में हवा के रुख में बदलाव हो गया है। अब दिल्ली की तरफ आने वाली हवा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके और पाकिस्तान के मध्य की ओर से आ रही है। इन क्षेत्रों में काफी गर्मी है और हवा शुष्क है। इसी के चलते दिल्ली में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि भीषण गर्मी का यह दौर लंबा नहीं खिंचने वाला है। पालावत बताते हैं कि बुधवार के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा। इससे धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली में दिन जहां झुलसाने वाले हो रहे वहीं रात की गर्मी भी लोगों को बेचैनी महसूस करा रही, चार दिनों में सात डिग्री चढ़ा तापमान

# दो दिन सताएगी गर्मी, 44° पहुंच सकता है पारा

**मौसम का मिजाज**

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली बारह दिन बाद भीषण गर्मी की चपेट में है। खासतौर पर पिछले चार दिनों में तापमान में सात डिग्री से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में इस समय दिन जहां झुलसाने वाले हो रहे हैं, वहीं रात की गर्मी के चलते भी लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है। दिल्ली में अगले दो दिन पारा 44 डिग्री तक भी पहुंच सकता है।

पिछले चार दिनों से मौसम की कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई। रविवार को एक बहुत ही छोटे इलाके में तेज आंधी और हल्की बारिश हुई थी। जिसका पूरी दिल्ली के तापमान पर खास असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 27 मई के बाद अब जाकर दिल्ली का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। दिल्ली के लोगों के लिए स्थिति ज्यादा परेशानी भरी इसलिए है क्योंकि दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान भी सोमवार को सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

**रिज का इलाका रहा सबसे ज्यादा गर्म :** राजधानी दिल्ली का रिज क्षेत्र सोमवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि, लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

**तेज गर्मी के लिए तैयार रहें :** दिल्ली के लोगों को अगले दो दिनों के बीच और भी भीषण गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जबकि, न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी रह सकती है। हवा तेज होने के चलते लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

**पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा राहत :** बुधवार के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता दिखेगी। इसके चलते 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज धूल भरी आंधी आ सकती है। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं।

## गर्मी में राहत दे रहे बांस से बने 'कूलिंग जोन'

राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीटवेव से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए बवाना में पर्यावरण-अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है। यहां बैठकर लोग हीटवेव से राहत पा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि लोगों को राहत देने वाले ऐसे पर्यावरण अनुकूल कूलिंग जोन दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में बवाना और अलीपुर में ऐसे दो कूलिंग जोन संचालित हैं। जल्द ही तीन और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं। इन कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और धूप में काम करने वाले अन्य लोगों को तेज गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है।

राजधानी में तेज गर्मी के बीच लोगों को राहत दिलाने के प्रयास भी हो रहे हैं। दिल्ली सरकार की 'बीट द हीट' पहल के तहत कनॉट प्लेस में रखे मिट्टी के घड़ों से शीतल जल लेकर अपनी प्यास बुझाते लोग। • संजू भट्ट

## आगे बढ़ रहा मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून की उत्तरी सीमा अरब सागर के कुछ और हिस्सों समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में प्रवेश कर चुका है। अगले दो से तीन दिनों में पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

## दक्षिण में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नौ से 11 जून के बीच लू की चेतावनी जारी की है।

## 11 को आंधी के आसार

11 और 12 जून को उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी, तेज हवा चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है।

# सफदरजंग संभालेगा नजफगढ़ स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र

**राहत**

■ रणविजय सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी) का संचालन सफदरजंग अस्पताल के सेटेलाइट सेंटर के रूप में होगा, ताकि इसमें डॉक्टरों की कमी दूर हो सके।

अस्पताल रोटेशन के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर नियुक्त करेगा। इससे आरएचटीसी में जल्द ही वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। इससे आरएचटीसी में आईपीडी (इंडोर पेशेंट सर्विस), ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम इत्यादि का संचालन शुरू हो सकेगा। साथ ही, मरीजों को भर्ती लेने, सर्जरी, गर्भवती महिलाओं के प्रसव, बच्चों के इलाज इत्यादि की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। इससे नजफगढ़, इसके आसपास के अनधिकृत कॉलोनियों और गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

**42** हजार से ज्यादा मरीज अभी आरएचटीसी की ओपीडी में प्रति माह पहुंच रहे

**7744** पीड़ित हर महीने इमरजेंसी में दिखाने के लिए आ रहे

## दो वर्ष के लिए घोषित किया गया सेटेलाइट केंद्र

- पांच मई को आरएचटीसी को दो वर्ष के लिए सेटेलाइट केंद्र घोषित किया गया है।
- यह व्यवस्था आरएचटीसी में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों को भरने में मदद करेगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है।
- 179 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर संविदा पर नियुक्त किए जाने हैं, जिसमें आरएचटीसी के 30 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों भी शामिल हैं।
- नियुक्ति के लिए सफदरजंग अस्पताल में इसी माह 15 से 25 जून के बीच साक्षात्कार होंगे।
- नियुक्त होने वाले सभी डॉक्टर रोटेशन के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर सफदरजंग अस्पताल से आरएचटीसी भेजे जाएंगे।

## असुविधा का करना पड़ रहा सामना

मौजूदा समय में नजफगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र जाफरपुर में सिर्फ एक राव तुलाराम अस्पताल है। इस वजह से नजफगढ़ और इसके आसपास के इलाके के लोगों को इलाज में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर आरएचटीसी में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाना है। इसके मद्देनजर भवन बनकर काफी पहले तैयार हो गया। इसमें ओपीडी सेवाएं भी संचालित हो रही हैं। ओपीडी में प्रतिदिन करीब डेढ़ हजार मरीज पहुंचते हैं। अभी तक आईपीडी, ऑपरेशन थियेटर और लेबर रूम की सुविधा शुरू नहीं हो पाई।

## विशेषज्ञों के पद पर सेवानिवृत डॉक्टर नियुक्ति

आरएचटीसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर के लिए फिलहाल सेवानिवृत डॉक्टरों की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा इसमें रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर के करने के लिए जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम भी शुरू हो सकता है। इसके तहत इसमें सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) इन तीन केंद्रीय संस्थानों से यहां रेजिडेंट डॉक्टर भेजे जाएंगे। ताकि इसमें रेजिडेंट डॉक्टर नियमित उपलब्ध रहे। हालांकि, इसमें चिकित्सा सेवाओं के संचालन की कमान आरएचटीसी प्रबंधन के ही हाथ में रहेगी।

बचने के लिए पहले बाजार में

लिए इन लोगों ओरल हायरिंग केब का इस्तेमाल किया। अपार्टमेंट में जाते समय आरोपियों

पार करने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो लिया।

मामले

# लू चलने से दिल्लीवासी हुए बेहाल 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा

अमर उजाला ब्यूरो

**नई दिल्ली।** लू चलने से दिल्लीवासी बेहाल दिखे। सोमवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तापमान भी 29.2 डिग्री पार कर गया। इस कारण रात में भी लोगों ने बेचैनी महसूस की। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उसके बाद 11 और 12 जून को आंधी और हल्की बारिश लोगों को राहत देगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 11 जून और 12 जून को दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर और रात के समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही हल्की बारिश भी होगी। इसके असर से तापमान में तीन से चार डिग्री कमी आने की संभावना है।

हालांकि, नौ जून और 10 जून को कड़ी धूप और लू चलने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्लीवासियों को सोमवार को लू ने खूब परेशान किया। इस दौरान लोगों ने धूप से बचने के लिए छाते आदि का प्रयोग किया।

धूप से बच्चे को बचाती महिला। एजेंसी

पूर्व कर्मी ने किराये पर

बायोडाटा की फोटो से लड़कि

# No mother should lose her life in childbirth

Every safe pregnancy is a reflection of a nation's commitment to its women. In a country with nearly 2.9 crore pregnancies annually, ensuring safe motherhood at scale requires robust health systems, sustained political commitment, timely interventions, and equitable access to quality health care services.

The remarkable decline in maternal mortality over the past decade — among India's most significant public health achievements — has been driven by sustained investments in maternal health, strengthened service delivery systems, community participation and a relentless commitment to ensuring that every woman has access to quality care throughout her pregnancy. At the heart of this transformation is the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA), completing its tenth year on June 9, a nationwide movement to provide assured, comprehensive and quality antenatal care services, free of cost, to all pregnant women on the ninth day of every month during the second and third trimesters of pregnancy.

JP Nadda

By dedicating the ninth day of every month to maternal health, the programme serves as a reminder that every pregnancy deserves continuous care, monitoring and support throughout the pregnancy period. One of the most important lessons in maternal health is that no pregnancy is entirely risk-free. Recognising that any pregnancy can become high-risk without warning, a simple yet transformative approach — identifying risks early, monitoring them closely and ensuring timely referral and management — was introduced. Every high-risk pregnancy (HRP) identified represents an opportunity to prevent a maternal death, a stillbirth, a newborn complication or lifelong disability. The focus under the PMSMA shifted from treating complications to preventing them.

One of its defining strengths is the institutionalisation of a fixed-day, assured platform for specialist-led antenatal care. Pregnant women are screened for nearly 25 HRP conditions (including severe anaemia, hypertension, gestational diabetes, and infections) that threaten maternal and newborn survival if left undetected.

As evidence emerged that HRPs require continued monitoring beyond routine antenatal care visit by a specialist/medical officer the programme was strengthened further in 2022. Women with HRPs receive additional follow-up visits over and above the regular sessions to ensure timely management until safe delivery. Name-based tracking of HRPs was introduced and follow-up mechanisms up to the 45th day after delivery were strengthened, ensuring continuous care throughout pregnancy and the immediate postnatal period. Incentives for Accredited Social Health Activists (ASHAs) accompanying women with HRPs for additional visits have further bolstered referral compliance and continuity of care.

A centralised digital portal serves as the backbone of programme management, enabling real-time reporting of service delivery, name-based tracking of HRPs, monitoring of performance and evidence-based decision-making. Importantly, the platform also allows private-sector specialists and community volunteers to register and contribute.

The programme works in synergy with other maternal-health focussed government initiatives such as the Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK), and Surakshit Matritva Aashwasan (SUMAN), among several others. This has contributed to building a stronger continuum of care for women throughout pregnancy, childbirth and post-partum.

The tireless efforts of health personnel across levels, in community mobilisation, counselling, screening, referral and follow-up, have ensured that maternal health services reach women even in the most remote areas of the country. The impact is increasingly visible in national health outcomes. According to the Sample Registration System estimates for 2022-24, India's maternal mortality ratio (MMR) has declined to 87 per 100,000 live births — close to the Sustainable Development Goal target of MMR below 70 by 2030.

The National Family Health Survey (NFHS-6, 2023-24) reports that institutional deliveries have increased to 90.6% from 88.6% in NFHS-5 (2019-21), while antenatal care coverage has improved from 92.6% in NFHS-5 to 95.9% — more women are accessing essential maternal health services than ever before, enabling early detection of complications and timely interventions. This underscores the scale and effectiveness of India's maternal health programmes. Since the programme's launch in 2016, more than 7.5 crore antenatal check-ups conducted have enabled the identification of over 1.17 crore HRPs. These achievements represent millions of mothers whose lives — as well as those of their newborns — were protected through timely and quality health care services.

A simple but powerful belief, that no woman should lose her life while giving life, and no family should lose a mother to a preventable pregnancy-related complication, guides the programme. The need is to continue strengthening quality antenatal care, HRP tracking, midwifery-led services, digital innovations and equitable access to maternal health care. The experience so far has reaffirmed a simple truth. When every pregnancy is monitored, every risk is identified early, and every woman receives timely, respectful and quality care, maternal deaths become preventable rather than inevitable. The last ten years are a testament to what can be achieved when political commitment, empowered frontline workers, digital innovation, community participation and quality health care services come together with a singular purpose.

**The need is to continue strengthening quality antenatal care and equitable access to maternal health care.** REUTERS/FILE

*JP Nadda is Union minister of health and family welfare. The views expressed are personal*

## 7 LAKH STRANGERS, ₹47 CRORE, 1 LIFE

# The human chain that gave Rahim a second life

**From children's piggy banks and workers' wages to a woman's gold chain, Kerala turned blood money into a campaign that brought a man home from death row in Saudi Arabia**

Rajeev.R@timesofindia.com

As Machilakath Abdul Rahim steps out of Calicut International Airport at 7.15am on May 28, Eid Al Adha, he struggles to hold back tears. It's an emotional moment for the 44-year-old, from Feroke in Kozhikode, who has just completed a 20-year prison sentence — on death row — in Riyadh, Saudi Arabia. But it's not just the homecoming that has his eyes welling up; it's the people, not family, but strangers. Waiting patiently outside the airport are hundreds of people. He has never met them before, yet they are the ones who made it possible for him to leave confinement. They are the ones who carried his story in their hearts for years, parting with their hard-earned money and other valuables to raise funds for his release.

"My heartfelt thanks to everyone who stood with me and prayed for me," Abdul Rahim says, wading through the crowd into his car. It marks the end of a two-decade ordeal that had taken him from a small town in Kerala to a Saudi death row cell.

For Kerala, Abdul Rahim's return represented something far larger: the emotional culmination of one of the most remarkable public solidarity campaigns the state has witnessed in recent years. Over seven lakh people had contributed to the crowdfunding campaign that eventually raised Rs 47 crore to secure his release, far exceeding the Rs 34 crore required as "blood money" under Saudi law.

In many ways, Kerala's response reflected an ethos the state has long prided itself on — the belief that every life matters, irrespective of religion, caste, class or political identity. Daily wagers, schoolchildren, expats, homemakers, businessmen and pensioners had all contributed whatever they could.

Kerala's large-heartedness is not new. In 2021, Keralites had stepped in to crowdfund the costly life-saving gene therapy treatment for one-and-a-half-year-old Mohammed, who was suffering from spinal muscular atrophy. They raised Rs 46 crore, more than twice the Rs 18 crore needed to save the little boy. There have been many similar stories about ordinary citizens stepping in.

**Bizman Who Donated Rs 1 Cr**



**"What moved me to support the campaign was the belief that the blood money provision in Saudi law offered a real chance to save a human life. I was also certain that the people of Kerala would come together wholeheartedly for such a cause**

Bobby Chemmanur

### 20 Yrs In Saudi Jail

Rahim — who worked as an autorickshaw and school vehicle driver — was just 26 in 2006, when he travelled to Saudi Arabia looking for a job, and some financial stability for his family.

He found work in Riyadh with a Saudi family and was also tasked with caring for his employer's son, Anas Al Shahri, a child with disabilities. But tragedy struck within weeks. During a journey, when Rahim was driving the car, the child reportedly became agitated and asked him to jump the traffic lights. While responding to the situation, Rahim's hand accidentally struck a medical tube attached to the boy's throat, causing his death.

Though Rahim maintained that the incident was accidental, Saudi courts later convicted him of murder and sentenced him to death in 2012.

As hopes for his release faded over the years, support groups in Kerala and among the Malayali diaspora in the Gulf slowly began mobilising around his case. The breakthrough came when negotiations with the victim's family opened under provisions in Saudi law permitting blood money (diyah) settlements.

Eventually, the family agreed to pardon Rahim in exchange for 15 million Saudi Riyals — roughly Rs 34 crore. For Rahim's family, the amount seemed unimaginable.

What followed, however, became one of the most remarkable moments of collective solidarity in Kerala's recent history. The crowdfunding campaign to save Rahim, which started off on March 10, 2024, rapidly transformed into a mass humanitarian movement: from businessman Bobby Chemmanur, who donated Rs 1 crore, to children emptying their piggy banks. From auto drivers contributing a day's income, to Kudumbashree members in Kunnamangalam, who parted with a portion of their modest earnings. Even labourers in Gulf countries pooled money, even as mosque committees spread the campaign after prayers.



Abdul Rahim with his mother Fathima, 77, following his arrival in Kerala last month. Now 44, he was put in jail in Saudi Arabia in 2006 in connection with the death of his employer's son

### Snowballing Sentiment

By April 12 this year, Rs 47 crore was collected, from which the Rs 34 crore blood money was handed over to the family.

What endeared Rahim's story to people was that it was not just about one man imprisoned in a foreign land, but about the pain, uncertainty and loneliness woven into the lives of millions of non-resident Keralites. At its heart was also the silent anguish of a 71-year-old mother, who had spent nearly two decades praying and waiting for her son's return, fearing each day that she might never see him alive again. Above all, it became a story about the extraordinary capacity of ordinary people to come together for someone they had never met and fight to bring him home.

"I came to know about the plight of Rahim through newspapers and at that time only Rs 1 crore was collected," says Chemmanur, the single highest contributor. The jeweller and philanthropist not only contributed money but also took out a yatra from Thiruvananthapuram to Thrissur to raise funds for the cause.

He got together with district-level office bearers of the Boche Fans Charitable Trust, and decided to do a "Yachaka Yathra (Begging Journey)" from Thiruvananthapuram on April 8.

"What moved me to support the campaign was the belief that the blood money provision in Saudi law still offered a real chance to save a human life. I was also certain that the people of Kerala would come together wholeheartedly for such a cause," says Chemmanur, adding that he met Rahim after his return and promised to provide him a job in a jewellery outlet in Kozhikode.

But it was not just the wealthy who opened their wallets for Rahim. In Kollam, Sofi Benny parted with the only valuables she owned — her gold locket and a gold chain — all for helping save a stranger's life.

"I came to know about Rahim's case through social media posts saying he was on death row. I contacted a Dubai-based vlogger to check whether it was genuine, and he confirmed it was," says Sofi, who works at a salon in Karunagappally.

"What broke me was seeing Rahim's mother crying and saying that her only wish was to see her son one last time," she says, adding that her husband was also supportive about helping Rahim. Rahim acknowledged her gesture through a video call with her, promising to meet her soon.

K Suresh, chairman of the Rahim Legal Assistance Committee, which spearheaded the collection campaign, said people were especially generous during the month of Ramzan. "During the 27th night of the month of Ramzan, the 'Laylat ul Qadr', considered the holiest night in the Islamic calendar, around Rs 14 crore flowed to the account," Suresh says. "When the collection touched Rs 30 crore, we convened a press conference and asked people to stop sending money, but the flow of money continued, and we ended up collecting Rs 47.87 crore. After the payment of legal fees and all, we still have over Rs 11.5 crore in the account. We are planning to either take forward the activities of the trust registered as Rahim Niyama Sahaya Samithi or give the balance fund to the Chief Minister's Disaster Relief Fund (CMDRF)."

### Dedicated App

Tirurangadi MLA PMA Sameer, who was the auditor of the Samithi, said the campaign's transparency became crucial to its success. A dedicated digital platform — the Save Abdul Rahim App — developed by Malappuram based Spine Codes Solutions allowed contributors to track donations in real time, strengthening public trust and encouraging wider participation.

After the blood money was paid, the Saudi authorities revoked Rahim's death sentence on July 2, 2024. Yet, he had to complete a separate 20-year prison sentence. That sentence officially ended on May 20.

When Rahim arrived at his ancestral house, a huge crowd had gathered there, many coming straight from the mosque after the morning Eid prayers, even as some travelled long distances simply to catch a glimpse of the man whose life had become Kerala's collective cause. While people jostled to catch a glimpse of him or to shake hands, others stood silently in the crowd and in tears, overwhelmed that a homecoming which once seemed impossible had finally become real.

**Salon Worker Who Donated A Gold Pendant**

**"I came to know about Rahim's case through social media posts saying he was on death row. I contacted a Dubai-based vlogger to check whether it was genuine, and he confirmed it was. What broke me was seeing Rahim's mother crying and saying that her only wish was to see her son one last time**



Sofi Benny

When Rahim spoke, it was almost as if a dam had burst. For years, he lived among inmates facing murder charges, including prisoners who had spent decades behind bars. Some fellow inmates were eventually executed. "For nearly 18 years, I had no hope at all," he said. "Only during the last two years did a glimmer of hope emerge."

Later, talking about the campaign that brought him home, he said, "These people gave me a second birth". "No words can adequately thank them. I will remain indebted to them for the rest of my life. Seeing the crowds and television cameras outside the airport I was surprised and doubted if they were really waiting for me," Rahim said later, describing the moments after he'd just landed.

In the end, his story became more than the tale of one man returning home from prison. It became a reminder of the power of collective compassion — of a society deciding that somewhere inside a prison cell thousands of kilometres away one human life was still worth fighting for.

REC POWER DEVELOPMENT AND CONSULTANCY LIMITED
GLOBAL INVITATION (Through e-bidding Only)

NOTICE INVITING TENDER

# ‘हरित क्षेत्र समाप्त होते रहे तो दिल्ली में सांस लेना दूभर होगा’

- हाईकोर्ट ने भारतीय पोलो संघ की याचिका पर निचली अदालत को जल्द सुनवाई को कहा
- जयपुर पोलो ग्राउंड से बेदखल करने के नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था

**नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता।** दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राजधानी में घटते खुले स्थानों और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसे ही हरित क्षेत्र खत्म होते रहे तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।

दिल्ली के प्रमुख हरित क्षेत्र जयपुर पोलो ग्राउंड से बेदखली के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भारतीय पोलो संघ की याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले को लंबित रखने के बजाय अंतरिम राहत के सवाल पर शीघ्र निर्णय जरूरी है।

याचिका में रेस कोर्स इलाके में स्थित 15.20 एकड़ क्षेत्रफल वाले जयपुर पोलो ग्राउंड से उसे बेदखल करने के सरकारी नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ ने दोनों पक्षों को दस जून को पटियाला हाउस कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश होने को कहा। पोलो संघ ने अदालत से गुहार लगाई थी कि जब तक याचिका पर फैसला न हो, तब तक बेदखली पर रोक लगाई जाए।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल तत्काल बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार का पक्ष है कि यह जमीन रक्षा और अन्य सार्वजनिक जरूरतों के लिए आवश्यक है, जिसके तहत आसपास की अन्य संस्थाओं की जमीन भी वापस ली जा रही है। इसमें दिल्ली जिमखाना क्लब भी शामिल है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने विरासत संरचनाओं के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए गए। पोलो संघ ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने 20 मई के बेदखली आदेश को पहले ही जिला अदालत में चुनौती दी है, लेकिन वहां अंतरिम राहत पर सुनवाई टलती रही, जिसके चलते उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

senger terminal.

felled. DMRC will pl

# Focus on better sterilisation and vaccination for dogs: Activists

Neha.Mishra@timesofindia.com

**New Delhi:** Animal rights activists, academics and legal experts on Monday urged authorities to strengthen sterilisation and vaccination programmes for stray dogs rather than removing them from public spaces. The issue of street dog management stems from administrative failures and inadequate implementation of the existing laws, they argued.

At a press conference organised by Conference for Human Rights (India), the speakers cautioned against interpreting Supreme Court's May 19 judgment relating to the relocation of community dogs as an endorsement of their mass removal or confinement.

Expressing concerns that the order could be misused and weaken safeguards against cruelty to animals, they maintained that sterilisation and anti-rabies vaccination under the Animal Birth Control (ABC) programme remained the only scientifically validated, legally permissible and sustainable methods to manage stray dog populations.

The speakers urged authorities to formally reaffirm the ABC programme as the sole humane and lawful approach in accordance with Animal Birth Control Rules, 2023. They also called for the expansion of animal birth control infrastructure. Municipal authorities, they said, should undertake large-scale awareness campaigns and support local volunteer groups to facilitate its implementation and improve community participation.

The conference recommended the establishment of stronger monitoring and accountability mechanisms to ensure compliance with ABC Rules, transparent utilisation of funds and periodic assessment of programme outcomes.

Advocate Nanita Sharma said while the order did not define mechanisms to determine whether officials were acting in good faith or with mala fide intent. She questioned who would monitor the implementation process and ensure that relocated animals were not subjected to cruelty.

Anu Pandey, a professor at Delhi University, said students often played an important role in feeding, vaccinating and sterilising street dogs on the campus. She also highlighted "widespread misinformation" surrounding rabies and dog bites.

The activists said any policy response should place animal welfare at its centre. They warned that large-scale confinement could lead to other challenges, including overcrowding, increased disease transmission, stress among animals, and significant financial and logistical burdens on local authorities.

They claimed that sustained sterilisation and vaccination campaigns in Goa and Sikkim had improved the situation, while Jaipur and Karnataka were cited as examples of implementing ABC Rules alongside improved waste management practices and community participation.

Meanwhile, an international Buddhist delegation, accompanied by Aloka, the Indian stray known as the "peace dog", met activist Maneka Gandhi on Monday and emphasised the need to promote peace, compassion and humane treatment of animals for a more harmonious world.

# दावा : मच्छरों के डंक से रक्षा करेगा 'स्टार होम'

## मलेरिया के मामलों में करीब 44 फीसदी तक देखी गई कमी

**प्रयोग**

**डोडोमा, एजेंसी।** मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए तंजानिया के वैज्ञानिकों ने अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है।

उन्होंने खास तरह के दो-मंजिला घर बनाए हैं, जिन्हें 'स्टार होम' नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन आधुनिक और सुरक्षित घरों की वजह से मलेरिया के मामलों में 44 फीसदी (लगभग आधी) तक की कमी देखी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, पारंपरिक घर अक्सर बंद और कम हवादार होते हैं, जहां मच्छर आसानी से छिप जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए घरों को एक विशेष डिजाइन के तहत तैयार किया गया है। खिड़कियों और दरवाजों को इस तरह बनाया गया है कि मच्छर चाहकर भी अंदर दाखिल नहीं हो पाते।

### कैसे होगा फायदा

दो मंजिला घर खासतौर पर मलेरिया से बचाव के लिए डिजाइन किए गए हैं। दीवारें, छत और दरवाजे-खिड़कियां ऐसे बनाई गई हैं कि मच्छर अंदर नहीं घुस पाते। चूल्हे से निकलने वाला धुआं अंदर नहीं रुकता, जिससे सांस की बीमारियों से बचाव होता है।

### भारत के लिए एक उम्मीद

जानकारों के अनुसार, भारत में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाए तो कीटनाशकों और दवाओं पर निर्भरता कम होगी, स्वास्थ्य व्यय घटेगा और गरीबों को स्वस्थ घर मिल सकेगा। सोलर लाइटिंग के कारण इलाकों में भी फायदा होगा। यह सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जो मलेरिया मुक्त भारत लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

### मलेरिया की स्थिति

भारत सरकार के 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' के कारण 2026 में मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। हमारा देश अब डब्ल्यूएचओ के 'हाई बर्डन' वाले देशों की सूची से बाहर हो चुका है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक इसके संक्रमण को शून्य करना और 2030 तक देश को मलेरिया-मुक्त बनाना है।

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

TIMES NATION
THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI | TUESDAY, JUNE 9, 2026

CORE OF CHANGES SINCE NDA
DI ON 12TH ANNIV OF GOVT

ASSAM CM HIMANTA UNVEILS POR
MINISTERS, COMPLETES FIRST CAB

# Times have changed, premarital sex not moral turpitude, says SC

## 'It's No Reason To Draw Inferences About Person's Character'

AmitAnand.Choudhary
@timesofindia.com

**New Delhi:** Citing the changing times and acknowledging the reality that premarital sex has become common, Supreme Court has said that being in such a relationship cannot be termed as moral turpitude to draw adverse inferences about a person's character. The authorities must keep in mind this reality and not initiate punitive action on such grounds, it held.

A bench of Justices Manoj Misra and Manmohan came to the rescue of an aspiring police official whose provisional selection in the force was cancelled on the ground that he had been in a physical relationship with a girl, and she had later filed a complaint against him. Though the girl had reached a compromise with him and the matter got settled in Lok Adalat, Telangana govt said the man stood disqualified as he was involved in an offence involving moral turpitude.

Telangana HC also ruled against him, saying he was indicted for an offence involving moral turpitude and the compromise did not amount to a clean acquittal.

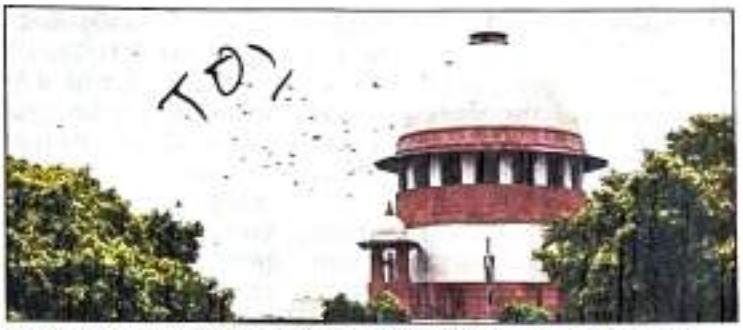

'There is no law which prohibits two consenting unmarried adults from having a relationship of their choice...' the bench said

Rejecting the plea of the state govt and also the HC's findings, SC quashed the govt decision and paved the way for the man's recruitment in the force. The court made it clear that engaging in premarital sex could not be a reason to bar the petitioner from the force. It pointed out that the victim herself had decided not to step into the witness box to depose against him.

"Besides, authorities would have to be sensitive to the changing times in the context of premarital relationships. Such premarital relationships are common today. Moreover, a physical relationship between two consenting unmarried adults cannot and should not by itself be a ground to draw an adverse impression about the character of the person in that relationship. There is no law which prohibits two consenting unmarried adults from having a relationship of their choice..." the bench said.

It highlighted that in a relationship which spans a considerable period, the court has time and again quashed criminal proceedings initiated by one party against the other on the ground that the victim was lured into a physical relationship under a false promise of marriage because there would be a presumption that such a relationship was based on valid consent.

In this case, the petitioner had truthfully revealed that the complaint had registered a case against him and also told the authority that the case was amicably settled in Lok Adalat. He said that he had been in a consensual relationship which did not result in marriage, and a case was registered after he married another girl.

The state, however, said police are a disciplined force and "the slightest doubt about the character of a candidate emanating from his past antecedents can be the basis to deny appointment".

Rejecting the state's stand, SC said, "Whether the prosecutrix was deceived into entering a relationship, she alone could have disclosed. The public at large cannot tell whether she was deceived. In such circumstances, when the prosecutrix chose not to pursue and had led no evidence, rather had expressed her consent to compound the case, there was no occasion for the respondents (state and others) to read between the lines and draw an adverse inference regarding the character of the appellant."

# लेडी हार्डिंग अस्पताल में अब होगी रोबोटिक सर्जरी

नई दिल्ली। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मरीजों को जल्द रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी। सर्जरी के लिए रोबोट खरीद को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इस साल के आखिरी तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। यह सुविधा निशुल्क मिलेगी।

सर्जरी विभाग में निदेशक प्रोफेसर डॉ. मनोज एंडले ने बताया कि सर्जरी के लिए रोबोट खरीद संबंधी प्रक्रिया का 80-90 फीसदी कार्य पूरा हो गया है। अगले छह महीनों में अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए अस्पताल की नई इमारत में आठवीं मंजिल पर खास ऑपरेशन थियेटर तैयार किया गया है।

डॉ. मनोज एंडले ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के लिए अलग-अलग सर्जन को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जब सर्जरी के लिए रोबोट उपलब्ध होगा तो उससे पहले भी एम्स दिल्ली की मदद से दोबारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो

SUKHMANI MALIK

# No escaping manosphere for women — and men

WOMEN ARE sick of the manosphere. And many want out — even if it is into a fantasy where men treat them with respect. The explosion of one show and one movie, both about desire and women's agency, in the last month is evidence: *Off Campus*, adapted from Elle Kennedy's book series of the same name, and Curry Barker's *Obsession*. Made on shoestring budgets, poles apart tonally, both are surprise hits. While *Off Campus* portrays the fantasy of romance, *Obsession* is its most horrific representation, but both aim to address reality.

*Off Campus* is the story of a handful of college students' trysts with love, friendship, family, and ambition. Viewers — especially women — are eating it up. It is another in the long list of shows and movies that constitute the on-screen romance renaissance; recent years have seen a significant surge in romance shows and movies in the West. But why?

In *Off Campus*, the main draw is the men. They are college students and hockey players, yet there is no "locker room talk". In a time when an alarming number of men are congregating in the "manosphere" and mistaking misogyny for masculinity, these male protagonists are caring and attentive partners and people, in touch with their own feelings and others'.

For many men and boys today, the strongest influences are figures like Donald Trump and Andrew Tate (both under investigation and/or convicted of sexual assault). This does not bode well for anybody. The echo chambers of the "manosphere" amplify the delusional narrative that young boys and men are somehow both perpetual victims and inherently more powerful than women. Qualities like sensitivity and respect are derided, cutting off the most organic routes to connection, the lack of which drives many men into the manosphere in the first place.

The success of shows like *Off Campus*, *Heated Rivalry*, and *Bridgerton* also suggests that these standards are hardly being met by men today. This is why the bare minimum has become a fantasy. The "romance renaissance" reflects, in reality, a lack of agency, respect, hope, and compatibility for women. What many men and women think constitutes a good relationship today — or even an appropriate performance of gender — is increasingly divergent.

For most women, the world is a scary place right now. Violence against them is on the rise, young men are more likely to lean conservative than many in the generations before them, there is a rollback in legal protections globally, and it often seems as though young women and men are living in different realities. No wonder there is a desire to escape into fantasy.

**Success of 'Off Campus' suggests that standards are not being met by men today. This is why bare minimum becomes fantasy. The 'romance renaissance' reflects a lack of agency, compatibility**

Which brings us to *Obsession*. The movie, a horror film focused on incel-culture, deals with the deficit of empathy and the spike in male entitlement. It captures how harmless and routine this attitude can look and how it escalates. Look closely at the film, and you'll notice: The violations were always there. Even when Bear (Michael Johnston) seemed to be just a "nice guy" with a crush on a girl in his friend circle, his obsession with winning Nikki's (Inde Navarrette) love had everything to do with him and nothing at all with her. This is why he feels comfortable, from the beginning, in denying her agency and, in the end, any mercy — all while playing the victim. When a section of society is raised to think of another as secondary to their needs, this is the result: Rejection becomes unacceptable, unrequited love becomes humiliation.

When the credits roll, it is to the walls of a bleeding, traumatised woman. The damage is apparent; it also does not discriminate — the entitled, the alphas, suffer and break just as hard as the women and people they subject to violence.

In the hardening of their attitudes, many men risk losing their humanity. While that is a worrying reality for women and society, it leaves the men depleted, too. There is no escaping the manosphere. The best we can hope for is a mass exit into reality. Until then, it will keep ending this way — with no winners at all.

*The writer is sub-editor, The Indian Express.*
*sukhmani.malik@expressindia.com*

effluent treatment plants

hal Lal, jal shakti minister C R

Corporation of Delhi (MCD)

"Nearly 97% of the estimated

# Fallout: Women account for 3/4th of elderly fracture cases at AIIMS

Anuja Jaiswal
@timesofindia.com

**New Delhi:** Elderly women account for a majority of serious fall-related fractures, with nearly three-fourths of patients treated at a specialised fracture clinic at AIIMS being women, institute data show.

Figures from the Fragility Fracture Liaison Service clinic at the Jai Prakash Narayan Apex Trauma Centre show that 822 patients were treated between Nov 2023 and Nov 2025. Of these, 596 were women and 226 were men.

Doctors said the data highlight the growing burden of osteoporosis-related fragility fractures among elderly women as India's population ages.

Contrary to the perception that such injuries mainly affect the very elderly, the largest share of patients was in the 60-69 age group (33.2%). This was followed by those aged 50-59 (31.6%) and 70-79 (24.9%).

The clinic, headed by Prof Vijay Sharma of the dept of orthopaedics, found that hip fractures were the most common injury, accounting for 330 cases (40.1%). Wrist fractures followed with 203 cases, followed by shoulder (84), spine (46) and other fractures involving the foot and hand.

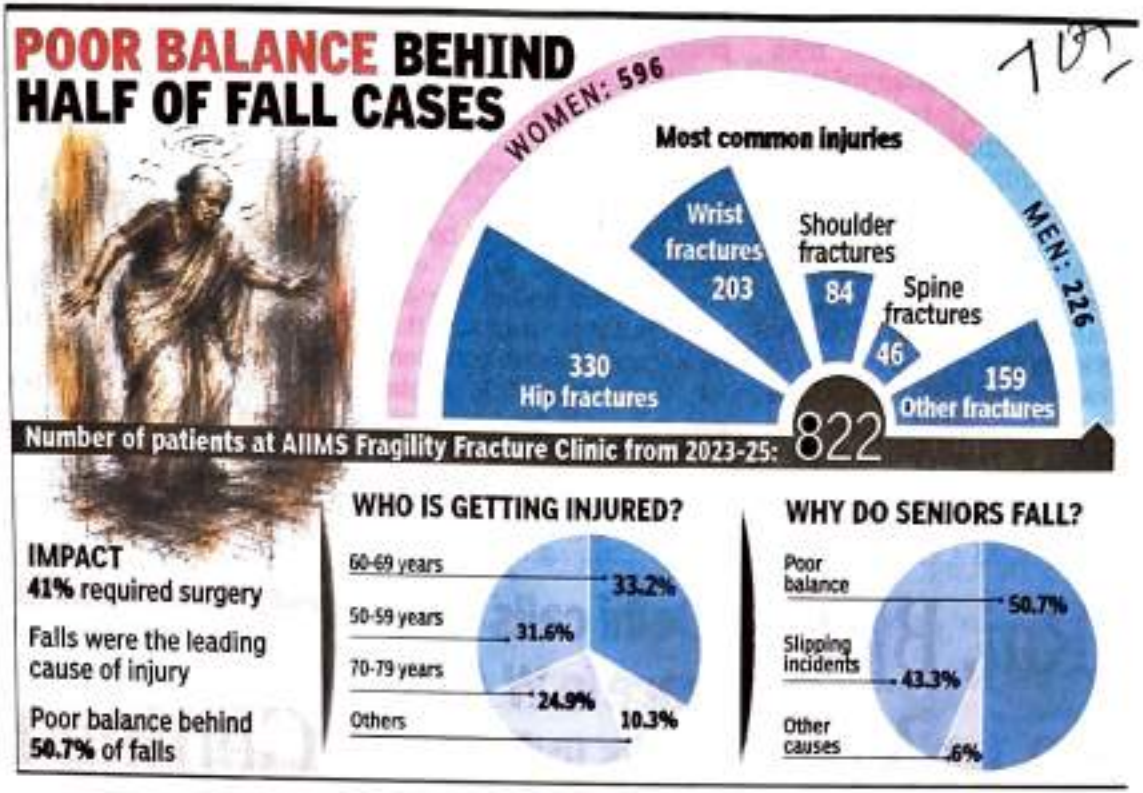


Falls were the leading cause of injuries among senior citizens. Poor balance emerged as the main risk factor, accounting for over half the cases, followed by slipping.

The data also point to the severity of these injuries, with around 41% of patients requiring surgery.

The clinic also noted that cases tend to rise between May and July each year, though no major increase in overall trauma cases was recorded during the two-year period.

AIIMS doctors said early treatment and rehabilitation are critical to prevent long-term disability. Timely surgery and early mobilisation help patients recover faster, avoid complications and regain independence.

Prof Kamran Farooque, chief of AIIMS Trauma Centre, said India is seeing a rise in geriatric orthopaedic trauma as life expectancy increases.

"Fragility fractures linked to osteoporosis are becoming more common among the elderly. As the population ages, such injuries will account for a larger share of trauma cases. We need a holistic approach that focuses not only on treatment but also on prevention, home safety, rehabilitation and osteoporosis management," he said.

To order your favourite newspaper, call 1800 1200 004 toll free or visit subscribe.timesofindia.com. To advertise v

**PLATEAUING OF SALES EARLIER THAN EXPECTED**

# Rush for Anti-Obesity Generics Thinning Down

Semaglutide drugs' unit growth slumps to 12% on-month in May, from 88% in April

**Rica Bhattacharyya**

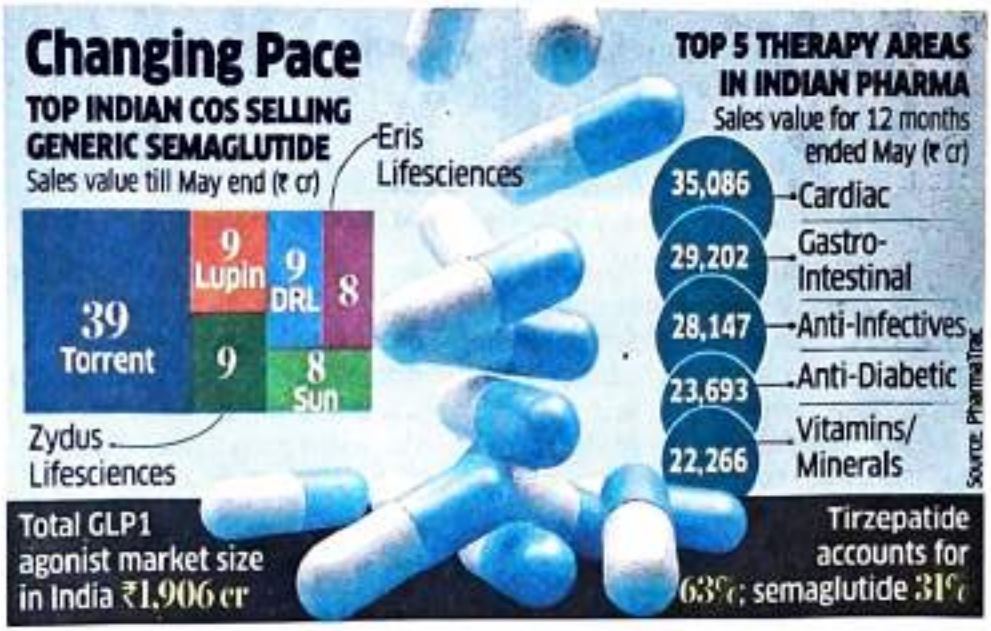


**Mumbai:** After explosive growth triggered by generic semaglutide launches in March, India's GLP1 anti-obesity market looks to be entering a phase of more moderate expansion, with sales of non-proprietary equivalents plateauing after the initial rush, based on data from market tracker PharmaTrac. The early affordability-led surge has eased, with on-month unit growth for semaglutide (oral as well as injectables) slowing to 12% in May, from as much as 88% in the previous month.

"The strong momentum shown by the market in April has slowed down in May after the first wave of eligible patients was onboarded following launch of lower-cost alternatives," said Sheetal Sapale, vice president, commercial, PharmaTrac.

The flattening has happened earlier than is typical of generic launches — sales usually take three to four months to stabilise.

A key factor is original patent holder Novo Nordisk slashing prices of its semaglutide products Ozempic and Wegovy just as generics sought to swamp the market.

Doctors said generic-semaglutide demand has moved beyond early adopter surge and is now entering a slower, education- and infrastructure-driven growth phase. Physician training, patient counselling and affordability will be key determinants of future uptake, they said.

Similar Prices ▸▸ 10

To order your favourite newspaper, call 1800 1200 004 toll free or visit subscribe.timesofindia.com. To advertise

**PLATEAUING OF SALES EARLIER THAN EXPECTED**

# Rush for Anti-Obesity Generics Thinning Down

Semaglutide drugs' unit growth slumps to 12% on-month in May, from 88% in April

**Rica Bhattacharyya**

**Mumbai**: After explosive growth triggered by generic semaglutide launches in March, India's GLP1 anti-obesity market looks to be entering a phase of more moderate expansion, with sales of non-proprietary equivalents plateauing after the initial rush, based on data from market tracker PharmaTrac. The early affordability-led surge has eased, with on-month unit growth for semaglutide (oral as well as injectables) slowing to 12% in May from as much as 88% in the previous month.

"The strong momentum shown by the market in April has slowed down in May after the first wave of eligible patients was onboarded following launch of lower-cost alternatives," said Sheetal Sapale, vice president, commercial, PharmaTrac.

The flattening has happened earlier than is typical of generic launches — sales usually take three to four months to stabilise.

A key factor is original patent holder Novo Nordisk slashing prices of its semaglutide products Ozempic and Wegovy just as generics sought to swamp the market.

Doctors said generic semaglutide demand has moved beyond early adopter surge and is now entering a slower, education- and infrastructure-driven growth phase. Physician training, patient counselling and affordability will be key determinants of future uptake, they said.

**Similar Prices ›› 10**

**CENTRES' NET EMPLOYEE ADDITION OF 200K VS 110K BY IT COS IN FY26**

{ NO PROHIBITION UNDER LAW }

# 'Consensual pre-marital relationships no stain on character': SC orders man's appointment as cop

**Utkarsh Anand**
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Pre-marital physical relationships between consenting adults cannot be treated as evidence of questionable character, the Supreme Court has held, observing that such relationships are increasingly common in contemporary society and are not prohibited by any law.

The court said that while character verification is an important component of recruitment , the exercise cannot be reduced to an assessment based on personal notions of morality.

**RECRUITMENT CAN'T BE REDUCED TO ASSESSMENT BASED ON PERSONAL NOTIONS OF MORALITY, SC SAID**

What is relevant is whether the conduct in question discloses criminality, dishonesty, violence or traits incompatible with public service, it added.

A bench of Justices Manoj Misra and Manmohan observed that modern society increasingly witnesses consensual relationships between unmarried adults and, in the absence of any legal prohibition, authorities cannot presume that participation in such a relationship reflects adversely on a person's integrity or character.

"Physical relationship between two consenting unmarried adults cannot and should not by itself be a ground to draw an adverse impression about the character of the person in that relationship. There is no law which prohibits two consenting unmarried adults to have a relationship of their choice," the bench said in its recent judg-

continued on →13

Follow us facebook.com/thehindu X.com/the_hindu instagram.com/the_hindu

# What is lost and gained in NFHS-6

NFHS-6 records gains in child nutrition, maternal care, institutional births and women's Internet use, while also introducing new questions on digital literacy and direct benefit transfers but the survey's preliminary fact sheet is thinner than the last round, dropping key indicators such as anaemia, mortality, sex ratio at birth

ECONOMIC NOTES

Areena Arora

India's latest National Family Health Survey (NFHS-6) records gains in child nutrition, maternal care, institutional births and women's Internet use. But its preliminary fact sheet is also thinner than the last round, with 101 indicators compared with 131 in NFHS-5.

**Which indicators were removed from NFHS-6?**

Key indicators such as anaemia, mortality, sex ratio at birth, sanitation, and clean cooking fuel have been removed from the survey.

The Union Health Ministry released the fact sheets of NFHS-6 on May 29, covering 2023-24. The survey recorded data from nearly 6.8 lakh households across every State and Union Territory except Manipur.

Preliminary findings report clear gains on several measures, including mothers getting at least four antenatal check-ups, up about seven percentage points from NFHS-5, an increase in institutional births and women's Internet usage. It also points to declines in several metrics, such as exclusive breastfeeding of infants under six months, down nearly eight percentage points, and the use of modern contraception, down to 52.7% from 56.4%.

The NFHS is commissioned by the Ministry of Health and Family Welfare, which designates the International Institute for Population Sciences (IIPS) to conduct the survey. Over the years, the scope of the survey has been additive by design, retaining the previous questionnaire and adding to it.

NFHS-4 in 2015-16 introduced district-level estimates and tablet-based digital interviewing for survey collection. NFHS-5 pushed the indicators further, including new topics, such as preschool education, disability, access to a toilet facility, death registration, bathing practices during menstruation and methods and reasons for abortion. It also recorded blood pressure and blood sugar measurements from adults aged between 15 and 49 to all adults aged 15 and above. The survey measured 131 key indicators, up from 114 in NFHS-4.

While the HIV testing component was dropped from NFHS-5, it retained questions on HIV/AIDS knowledge, attitudes, prior testing, sexually transmitted infections, and sexual behaviour. In NFHS-6, biological HIV testing has been brought back as part of the clinical, anthropometric and biochemical testing schedule.

The NFHS-6 fact sheet does not separately spell out whether all HIV/AIDS knowledge and attitude questions were retained.

NFHS-6 also added new questions on direct benefit transfers, self-help group memberships, digital literacy and financial transactions. It also includes testing for Hepatitis-B and Hepatitis-C among women and men, as well as dried blood spot collection from children aged 6-59 for Hepatitis-B testing.

But for the first time, the survey has also subtracted overall, showing a net reduction of 30 indicators in the preliminary results. Among the dropped indicators, the most notable ones, such as anaemia, infant and child mortality, sex ratio at birth, clean cooking fuel use, and sanitation, have all appeared since at least NFHS-4.

The NFHS is commissioned by the Ministry of Health and Family Welfare, which designates the IIPS to conduct the survey. GETTY IMAGES

**Why was anaemia dropped?**

The case for removing anaemia is related to how it was measured. The indicator had long shown a worsening picture. Between NFHS-4 in 2015-16 and NFHS-5 in 2019-21, anaemia rose across the board. Among children, anaemia prevalence went up from 58.6% to 67.1%, among women aged 15-49, it rose from 53.1% to 57%, and among pregnant women, anaemia rose from 50.4% to 52.2%.

The rise in anaemia was near-universal across the country, with child anaemia increasing in 28 States and Union Territories, and in some cases by big leaps, from 35.7% to 68.4% in Assam and 20.3% to 46.4% in Mizoram. Such deterioration was reported despite the government launching the Anaemia Mukt Bharat campaign in 2018, aimed at tackling anaemia. The reason for dropping it as an indicator then boiled down to how the data were being collected.

NFHS measured haemoglobin from a finger-prick blood sample read on a portable analyser, which several nutrition researchers contend overstated anaemia compared to the venous blood drawn by other surveys. IIPS dropped the anaemia questionnaire when NFHS-6 fieldwork began in 2023. The official position is that the condition will now be tracked separately, through a dedicated Diet and Biomarkers Survey under the National Institute of Nutrition using a method its proponents consider more accurate.

The Diet and Biomarkers Survey in India was not a hurried replacement and was launched in December 2022, before NFHS-6 fieldwork began, at the ICMR-National Institute of Nutrition in Hyderabad.

The survey recorded data on individual dietary intake across age groups, paired with blood and urine biomarkers.

It also built upon nutrition deficiencies and tracked obesity alongside anaemia, a first, according to the organisers. For anaemia, data were collected from venous blood instead of the finger-prick method that NFHS used. Data collection is complete, but hasn't been released yet.

**What other changes were made?**

A line-by-line comparison of the two fact sheets from NFHS-5 and NFHS-6 shows that the net fall of 30 actually combines 43 indicators dropped and 13 added. Several of the deletions were long-running series, and a few are closely related to the government's signature programmes.

Prime Minister Narendra Modi's government in 2019 had announced that India would be open defecation-free. NFHS-5 recorded 70% of the country's population living in households with access to sanitation facilities. That data point has also been dropped.

The share of households using clean fuel for cooking, 58.6% in NFHS-5, a gains – a direct measure of the success of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.

The three mortality indicators – neonatal, infant and under-five – have also been cut, but these will be tracked by the Sample Registration System, whose latest bulletin put infant mortality at 24 per 1,000 live births.

The Registration System, however, does not carry district-level data and socio-economic breakdowns that are available in NFHS.

The sex ratio of the total population and the sex ratio at birth, 929 females per 1,000 males in NFHS-5, are both absent, removing a standard signal of sex-selective practices. Four cancer-screening indicators, covering cervical, breast and oral cancer, introduced only in NFHS-5 are gone after a single round.

A few changes are redefinitions rather than cuts. Women's individual ownership of a house or land has become a household-level measure. Three-dose hepatitis B line has become a birth-dose measure, and pre-school attendance has shifted age bands, targeting a younger demographic. IIPS has not published a rationale for the wider list.

Together, the removals leave no current survey-based national figure for infant mortality, sanitation coverage, sex ratio at birth, cancer screening rates or comprehensive HIV knowledge, gaps that no other single source fills at the same scale.

**How did survey results change between NFHS-5 and NFHS-6?**

NFHS-6 reported a drop in the number of women who have experienced spousal violence, down to 22.2% from 29.3%. The number of children aged five or below who are stunted declined too. The drop from NFHS-4 to NFHS-5 was just under three percentage points, but NFHS-6 saw a drop of over six percentage points.

State-level changes are sharper for certain indicators.

Health insurance coverage rose the most in West Bengal, from 33.7% of households in NFHS-5 to 88.2% in NFHS-6. Women's Internet use saw its largest increase in Andhra Pradesh, from 20% to 63.6%. Haryana recorded the steepest fall in exclusive breastfeeding among infants under six months, from 69.5% to 41.2%. The share of women classified as overweight or obese increased in every State.

## THE GIST

- NFHS-6 shows a net reduction of 30 indicators in its preliminary fact sheet, with 43 indicators dropped and 13 added compared with NFHS-5.
- Anaemia was dropped from NFHS-6, with the official position being that it will be tracked separately through the Diet and Biomarkers Survey.
- Several long-running indicators, including infant and child mortality, sex ratio at birth, sanitation coverage, clean cooking fuel use and cancer screening measures, are absent from the latest fact sheet, leaving gaps that no other single source fills at the same scale.